कोयले के लिए राज सहायता

992. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोयले की पूर्ति के संबंध में राज सहायता बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा) : (क) और (ख) साफ्ट कोक की उपलब्ध मात्रा को राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने के लिए आवंटित किया जा रहा है । घरेलू उपयोग के लिए साफ्ट कोक का मूल्य 1982 से 175 रु० प्रति टन निर्धारित किया गया है जबकि इसकी अनुमानित उत्पादन लागत लगभग 600 रु० प्रति टन है । इसकी उत्पादन लागत बढ़ जाने के बावजूद अभी तक आर्थिक सहायता कीमत को इसी स्तर पर बनाए रखा गया है ।

हरियाणा को कोयले की पूर्ति

993. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में कोयले की मांग और पूर्ति के बीच बहुत बड़ा अन्तराल है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयले की अपर्याप्त पूर्ति और अधिक ढुलाई लागत के कारण अनेक उद्योग बन्द हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो हरियाणा में किन-किन कोयला खानों से कोयले की पूर्ति की जा जा रही है; और

(घ) सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या पहल की है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा) : (क) और (ख) कोयले की मांग का मूल्यांकन क्षेत्रवार अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है और न कि इसका मूल्यांकन राज्यवार किया जाता है ।

हरियाणा में कोयला उपभोग क्षेत्र में कोयला की आपूर्ति में वास्तव में वर्ष 1990–91 में 26.76 लाख टन की तुलना में वर्ष 1991–92 में 38.69 लाख टन की वृद्धि देखने में आयी है । अप्रैल-सितम्बर, 1992 की अवधि में कोयले की आपूर्ति 21.60 लाख टन की गई है । रेल द्वारा गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं को रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति में कमी रही है । यह कमी महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे विद्युत, इस्पात, आदि में कोयले के संचलन को प्राथमिकता दिए जाने के कारण आई है ।

(ग) हरियाणा राज्य में कोयला की कोई खानें नहीं है ।

(घ) संयोजन के एवज में आपूर्ति किए जाने के अतिरिक्त, उपभोक्ता अपने कोयले की आवश्यकताएं सड़क द्वारा 1000 टन तक एक बार में किसी विशिष्ट कोलिरियों से बिना किसी प्रायोजकता के प्राप्त कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त काफी मात्रा में पिट हैड स्टाक से भी कोयले की पेशकश वास्तविक उपभोक्ताओं को तरजीह देने के साथ-साथ ग्राहकों को भी पेशकश की जा रही है । सभी उपभोक्ताओं को, जिनमें हरियाणा राज्य के उपभोक्ता भी शामिल हैं, कोयले की चालू वर्ष में उपलब्धता में वृद्धि किए जाने की संभावना है ।

Opening of new coal mines in Madhya Pradesh

994. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether is is a fact that South Eastern Coalfields India Limited has

decided to open some new coal mines in Bilaspur and Sarguja districts of Madhya Pradesh during the current financial year;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the quantity of coal that is likely to be obtained from such coal mines every month and the number of jobs that are likely to be created therefrom;

(d) whether Government have done any survey about the availability of coal in Surguja district of the State; and

(e) if so, what are the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA) : (a) to (c) Yes, Sir. Details are given below :

S. No.	Name of the mine	Annual targetted capacity (mtpa)	Monthly production on achieving capacity (in thousand tonnes)	Manpower provision (Nos.)
Bilaspur District				
1.	Dilwadih . . .	0.27	22.5	786
2.	Singhali . . .	0.24	20.0	840
Sarguja District				
3.	Pandavpara . . .	0.21	17.5	906
4.	Mahamaya . . .	0.27	22.5	1130
5.	Girijapur . . .	0.30	25.0	935

(d) and (e) According to the regional exploration carried out by Geological Survey of India (GSI) in Sarguja District (Madhya Pradesh) the total coal reserves established as on 1-1-1992 (down to a depth of 300 metres) is 1647.29 million tonnes.

Package for investment in coal sector

995. SHRI SHARAD MOHANTY : SHRI CHIMANBHAI MEHTA : SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN :

Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that German and Australian companies have been offered attractive package for investment in coal industry;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the Eighth Five Year Plan Production targets for the coal industry and expected shortfalls for matching financial resources;

(d) what is the budgetary support of the Central Government since last three years for coal sector; and

(e) what are the reasons for getting budgetary support and how long this would continue and what are the heads of account on which the support accrues ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA) : (a) and (b) German and Australian assistance has been agreed to for implementation of several projects in coal sector.

In addition to the on-going projects with German assistance i.e. Chinakuri Underground (Eastern Coalfields Limited), Bina Coal Preparation Plant (Northern Coalfields Limited), Ramagundam OC-II (Singareni Collieries Company Limited), Neyveli-II and Neyveli-III Projects, several other coal projects viz. Kalinga coal preparation plant, Identification of old abandoned mines, characterisation of coking coal, subsidence and strata control, second Mine Expansion and First TPS Expansion of Neyveli, Safety Investigation Sys-